IF UNDELIVERED
PLEASE RETURN TO
मारवाड़ का मित्र
:: Regd. Office ::
वैष्णव फार्म परावा,
जिला - जालोर (343041)

सांचौर (जालोर) से प्रकाशित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

मारवाड़ का मित्र

Www.MarwadkaMitra.in

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post Reg No. RJ/SRO/9657/2023-25 UDYAM-RJ-19-0033346

प्रकाश वैष्णव -प्रकाशक/संपादक 9602473302

वर्ष 23 | अंक 12 | सांचौर, रविवार 15 जून 2025 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव, | मूल्य वार्षिक 500 रुपये | कुल पृष्ठ - 4

तीन सहकारी समितियों में 500 मैट्रिक टन गोदाम की स्वीकृति जारी

जयपुर । प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भण्डारण योजना के तहत 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 500 मैट्रिक गोदाम का निर्माण करवाया जा रहा हैं, जिसके क्रम में सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय द्वारा पूर्व में दो जिलों की तीन समितियों के लिए जारी की गई गोदाम निर्माण स्वीकृति को निरस्त कर तीन जिलों में नई स्वीकृति जारी की गई हैं, जिसके अनुसार, हनुमानगढ़ जिले की खोड़ा के स्थान पर नागौर जिले की निमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति तथा भीलवाड़ा की धोरा का बडिया के स्थान पर सिरोही जिले की गोल, इसी तरह भीलवाड़ा जिले की दौलतपुरा के स्थान पर राजसमंद जिले की मोही ग्राम सेवा सहकारी समिति में 500 मैट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम निर्माण की स्वीकृति दी गई हैं ।

सहकारिता से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र को और बढ़ाना होगा

राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र को और बढ़ाना होगा-राज्यपाल

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र को और बढ़ाना होगा। राज्यपाल चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में चित्तौड़गढ़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित रजत जयंती वर्ष के उद्घाटन एवं बैंक के प्रधान कार्यालय भवन के शिलान्यास समारोह में संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र से कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने राजस्थान में सरकारी क्षेत्र को और बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि यहां इस सहकारिता क्षेत्र में दुग्ध डेयरी की अपार संभावनाएं हैं, इसमें गरीब भी दुग्ध व्यवसाय कर सकता है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को मार्केटिंग की जगह उपलब्ध करानी होगी, इसमें प्रशासन एवं सरकार सहयोग करें। इससे समितियां भी अच्छी चलेगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता को मन एवं दिल से चलाना होगा, तो इसके अच्छे परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि सभी महिला पुरुषों को रोजगार मिले ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। राज्यपाल ने कहा कि जिस राष्ट्र का वैभव बढ़ाना है तो वहां की बौद्धिक क्षमता और शारीरिक क्षमता को बढ़ाना होगा। इसके लिए नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों की बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता बढ़ानी चाहिए। उन्होंने ने कहा कि लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी करने एवं काश्तकार की फसल अच्छी हो इसके लिए आवश्यक है कि उसे काश्त करने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि गांव का पानी गांव में ही रोका जाना चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद सीपी जोशी ने त्याग, तपस्या एवं बलिदान की भूमि पर आगमन पर राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि चित्तौड़गढ़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ने नई तकनीक एवं अन्य बैंकों की तरह कार्य कर सफलता हासिल की है और यह अन्य जिलों में भी शाखाओं का विस्तार करेगी। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना है, यह गर्व का विषय है। इससे पहले राज्यपाल ने समारोह में चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के प्रधान कार्यालय भवन का शिला पूजन किया। प्रारंभ में बैंक के अध्यक्ष आईएम सेठिया ने राज्यपाल को मेवाड़ी पगड़ी पहनकर स्वागत किया और बैंक की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी।

लंबित पुराने प्रकरणों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं

धारा 55 एवं 57 के लंबित प्रकरणों की जांच निर्धारित समय अवधि में करें पूरी - सहकारिता प्रमुख शासन सचिव

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम-2001 की धारा 55 एवं 57 के तहत लम्बित प्रकरणों की जांच निर्धारित समय अवधि में पूरी कर जांच परिणाम जारी करने के निर्देश सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने अधिकारियों को देते हुए कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लम्बित पुराने प्रकरणों के निस्तारण में देरी कर रहे अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। श्रीमती राजपाल नेहरू सहकार भवन में वीसी के माध्यम से राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम-2001 की धारा 55, 57 (1) एवं 57 (2) के तहत लम्बित प्रकरणों की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने पुराने प्रकरणों के निस्तारण में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकारी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाकर प्रकरणों का शीघ्र निपटारा करें। स्पष्ट निर्देशों के बावजूद लापरवाही बरत रहे अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि केवल बार-बार नोटिस देकर प्रकरण को लम्बित नहीं रखा जाए। साथ ही, जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट तत्काल सबमिट की जाए। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि सहकारी समितियों में अनियमितताओं के प्रकरणों से आमजन का सहकारिता में विश्वास कम होता है। इसलिए जांच अधिकारी ऐसे प्रकरणों में पूरी ईमानदारी से जांच कर अपनी रिपोर्ट दें। वरिष्ठ अधिकारी भी यह ध्यान रखें कि पर्यवेक्षणीय लापरवाही नहीं हो। श्रीमती राजपाल ने निर्देश दिए कि नये प्रकरणों का भी मुख्यालय से जारी परिपत्र के अनुसार तीन माह की अवधि में आवश्यक रूप से निस्तारण किया जाए। साथ ही, माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों का भी शीघ्र निस्तारण करवाने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिक लम्बित प्रकरणों वाले तीन खण्डों (जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर) की जुलाई माह में फिर से समीक्षा की जाएगी। बैठक में अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) श्रीमती शिल्पी पांडे, संयुक्त रजिस्ट्रार (नियम) श्री अजय उपाध्याय एवं सहायक रजिस्ट्रार (मॉनिटरिंग) श्री शिरीष चांदे मौजूद रहे। जबकि, सभी अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड), जिला उप रजिस्ट्रार एवं संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम-2001 की धारा 55 एवं 57 के तहत लम्बित प्रकरणों की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती मंजू राजपाल ने की समीक्षा

869 प्रकरणों का किया गया निस्तारण

बैठक में एक वर्ष से कम, एक से तीन वर्ष, तीन से पांच वर्ष एवं पांच वर्ष से अधिक समय से लम्बित प्रकरणों की खण्डवार समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बैठक में अवगत कराया कि वर्ष 2024-25 में कुल 869 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिनमें धारा 55 के 249, धारा 57 (1) के 342 एवं धारा 57 (2) के 278 प्रकरण शामिल हैं। इसी प्रकार, वर्ष 2025-26 में 31 मई तक 94 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है, जिनमें धारा 55 के 20, धारा 57 (1) के 42 एवं धारा 57 (2) के 32 प्रकरण शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जयपुर, बीकानेर, जोधपुर एवं भरतपुर खण्ड में प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति अच्छी रही है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. बासड़ा धनजी

एक सब के लिए सब एक के लिए

सहकारी आंदोलन, किसानों एवं ग्रामीणों को समर्पित प्रगतिशील सहकारी सोसायटी

किसान भाई, अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा कर, ब्याज मुक्त योजना का लाभ उठावें। समिति कार्यक्षेत्र के पशुपालक, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए समिति स्तर पर संपर्क करें।

श्रीमती धीरेन्द्र कंवर
अध्यक्ष

पीराराम गर्ग
व्यवस्थापक

सहकारिता का ध्येय वाक्य 'एक सब के लिए, सब एक के लिए'सब '

आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने किया कार्यभार ग्रहण

जयपुर,। राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष श्री उत्कल रंजन साहू ने गुरूवार को मध्यान्ह पूर्व कार्यभार ग्रहण किया। आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री कैलाश चंद मीणा ने उन्हें कार्यभार सौंपा। सचिव श्री रामनिवास मेहता द्वारा उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यभार ग्रहण के बाद श्री साहू ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष पद का दायित्व चुनौतीपूर्ण है। उनके द्वारा इसके निर्वहन का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। परीक्षाओं व साक्षात्कारों का समयबद्ध आयोजन उनकी प्राथमिकता रहेगा। उन्होंने कहा कि आयोग की प्रक्रियाओं के संबंध में वर्तमान सदस्यों व अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर आगामी कार्ययोजना निर्धारित की जाएगी।

विभागीय आदेशों पर भारी पड़ रही शीर्ष सहकारी संस्था...

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । पिछले दिनों अलवर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारियों द्वारा दैनिक कार्य बहिष्कार के दौरान अलवर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक प्रबंध निदेशक द्वारा एक पत्र जारी किया गया, जिसके मुताबिक पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना में प्रतिबंधित ऋण को मुक्त किया जा सकता हैं । यह निर्देश राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक की ओर से वीसी के दौरान देना बताया गया हैं । हालांकि ऋण पर प्रतिबंध के लिए सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैकिंग) की ओर से आदेश जारी कर पैक्स कंप्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिती तक ऋण पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए थे । जबकि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक कई सालों से सहकारिता विभाग के हर आदेश पर भारी पड़ सुर्खियां बटोरती नजर आ रही हैं, ऐसी ही सुर्खियां इस बैंक ने कोरोना काल में चांदी के सिक्के बांट कर बटोरी थी । दरअसल वर्ष 2020 में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की आमसभा कोरोना काल में वर्चुअल तरीके से हुई, जिसमें सदस्य अपने जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे, इन सभी को उपहार के स्वरूप 250-250 ग्राम के चांदी के सिक्के दिए गए. चांदी के सिक्के सदस्यों के साथ ही विभाग के कई सदस्यों को भी थोक में बांटे गए थे । जबकि आमसभा में 21 सदस्य शामिल होने के बावजूद चांदी के सिक्के 40 से अधिक लोगों को तक़सीम कर दिए । इनमें 7 कलेक्टर भी शामिल थे, यह सभी कलेक्टर केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रशासक के तौर पर शामिल हुए थे ।

एफआईजी को लेकर लिखी गई लंबी चौड़ी बातों के पोस्टर और बैनर केंद्रीय सहकारी बैंकों से लेकर प्राथमिक कृषि ऋणदात्री समिति पर देखे जा सकते हैं...

बदलाव के बावजूद बदहाल

वर्ष 2019 में ऑनलाइन ऋण वितरण की पॉलिसी तैयार सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक को भेजी गई, जिसमें सहकारी फसली ऋण पोर्टल से ऋण वितरण की सुगम व्यवस्था को लेकर समिति स्तर पर फाइनेंशियल इन्क्लूजन गेटवे यानि एफआईजी लागू कर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कर बड़े-बड़े बैनर राज्यभर में केंद्रीय सहकारी बैकों और नेहरू सहकार भवन पर लगाए गए । लेकिन आज समिति स्तर पर इस फाइनेंशियल इन्क्लूजन गेटवे में सर्वर की समस्या को लेकर सीसीबी और नेता प्रतिपक्ष इसमें सुधार की गुहार लगा रहे हैं ।

तिथि बढ़ने के बाद भी मय ब्याज ऋण

राज्य सरकार की ब्याज मुक्त योजना के तहत वितरित ऋणों की वसूली अवधि 30 जून या एक साल जो भी पहले हो तक बढ़ाई गई थी, लेकिन खरीफ का ऋण चुकाने में देरी करने वाले किसानों को पैक्स कंप्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण ग्राम सेवा सहकारी समितियों की एफआईजी आईडी बंद होने के चलते आज मय ब्याज राशि चुकाने के पश्चात भी फाइनेंशियल इन्क्लूजन गेटवे में सर्वर समस्या से ऋण नहीं मिल पा रहा हैं ।

अनिल विश्नोई को मिला अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खंड जोधपुर का अतिरिक्त कार्यभार

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राजस्थान सहकारिता सेवा के संयुक्त रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी शुद्धोधन उज्जवल वर्तमान में अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खण्ड जोधपुर में पदस्थ हैं, उन्हें अपनी सेवा के 33 दिवस के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति मिली हैं । इस संबंध में सहकारिता विभाग संयुक्त शासन सचिव दिनेश कुमार जांगिड़ की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, उज्जवल को 33 दिवस उपार्जित अवकाश 26 मई से लेकर 27 जून की स्वीकृति मिली हैं, इस दौरान अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खंड जोधपुर का अतिरिक्त कार्यभार जोधपुर सीसीबी में प्रबंध निदेशक पद पर पदस्थ अनिल विश्नोई को सौंपा गया हैं, साथ ही उज्जवल के अवकाश से लौटने तक अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने के निर्देश दिए गए है

जिला स्तरीय स्क्रीनिंग चयन कमेटी जोधपुर द्वारा 134 कर्मचारियों को मान लिया गया पात्र

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जांच का मुद्दा फिर लेने लगा उबाल

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर । केंद्रीय सहकारी बैंक में नियमों की उल्टी गंगा बहाने का काम कई सालों से चल रहा हैं, इस सीसीबी में होती रहीं अनियमितिताएं की विभागीय जांचों में लीपापोती करने की परिपाटी सालों से निरंतर जारी हैं । गत समय में सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना में प्रीमियम की कटौती के पश्चात ग्राम सेवा सहकारी समितियों से ऋण लेने वाले किसानों का बीमा नहीं करने का प्रकरण भी विधानसभा में फलौदी विधायक पब्बाराम विश्नोई ने उजागर किया। अब इस केंद्रीय सहकारी बैंक में अधिशासी अधिकारी के पद पर पदस्थ राजस्थान सहकारिता सेवा की एक महिला अधिकारी पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां से रिश्वत लेने के आरोप भी सुर्खियों में छाए हुए हैं । इतना ही नहीं, हाल ही में सहकारी साख आंदोलन से जुड़े सूत्रों ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नियम विरुद्ध जिला स्तरीय स्क्रीनिंग चयन कमेटी के माध्यम से नियमितीकरण करने के आरोप लगाया हैं, इस संबंध में सूत्रों द्वारा सहकारिता विभाग प्रमुख शासन सचिव को एक शिकायती पत्र भेजकर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई हैं । उन्होने पत्र के जरिए बताया कि जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 10 जुलाई 2017 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों को स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमित करने के लिए सहकारिता विभाग पंजीयक द्वारा 28 जुलाई 2022 को एक आदेश जारी कर प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसके उपरांत जिला स्तरीय स्क्रीनिंग चयन कमेटी जोधपुर द्वारा 134 कर्मचारियों को मुख्य कार्यकारी (व्यवस्थापक) एवं मुख्य कार्यकारी (सहायक व्यवस्थापक) पद के लिए योग्य मान लिया गया । जबकि इनमें से अधिकतर कर्मचारियों की अधिकतम एवं न्यूनतम आयु स्क्रीनिंग की दिनांक तक पूर्ण नहीं होने तथा शैक्षिणक योग्यता एवं डी फैक्टो के साथ समिति स्तर पर आमसभा एवं मीटिंग में स्क्रीनिंग के लिए प्रस्ताव तक नहीं लेने के आरोप लगे हैं, इतना हीं नहीं, सूत्रों ने पत्र में अतिरिक्त रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी गठित कर नए सिरे से केवल जोधपुर जिला स्तरीय स्क्रीनिंग चयन कमेटी द्वारा संपन्न संपूर्ण कार्यवाही की जांच करवाकर स्क्रीनिंग में शामिल दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग उठाई हैं ।

विधानसभा में लाभ-हानि को लेकर किया तारांकित प्रश्न

सोलहवीं विधानसभा के तृतीय सत्र के दौरान जोधपुर केंद्रीय सहकारी बैंक की गत पांच वर्षों की लाभ-हानि का विवरण फलौदी विधायक पब्बाराम विश्नोई ने एक तारांकित प्रश्न अंकित कर विभाग से सदन के माध्यम से मांगा हैं, विधायक ने केंद्रीय सहकारी बैंक में हाउस लोन, सी सी लिमिट व्यक्तिग ऋण, मोरगेज ऋण वितरण एवं वसूली के साथ पूर्व में ऋण वितरण में हुई अनियमितताओं की जांच तथा दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण मांगा, लेकिन विभाग द्वारा आज दिन तक सवाल का कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया हैं ।

अवधिपार ब्याज राहत योजना से मिला किसानों को आर्थिक संबल

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, किसान अपने बेहतर कल के लिए फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए ऋण लेता है लेकिन कई बार मौसम और बीमारी की मार से फसल खराब हो जाती है और समय पर ऋण नहीं चुका पाता, ब्याज बढ़ता जाता है और उसे पुन: ऋण नहीं मिल पाता, वह दृष्चक्र में फंस जाता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील सरकार ने किसानों की इस समस्या का हल मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना-2025-26 से निकाला जिसमें अवधिपार ऋण राशि का मात्र 25 प्रतिशत जमा करवाने पर किसान को ब्याज में एकमुश्त राहत दी जाती है और वह पुन: ऋण लेने का पात्र हो जाता है। यह योजना जोधपुर समेत पूरे राज्य के किसानों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड से अब तक 36 किसानों ने 62.41 लाख रूपये की ऋण राहत प्राप्त की है। इन किसानों द्वारा अपेक्षाकृत बहुत कम राशि जमा करवाकर योजना के तहत ब्याज एवं दण्ड ब्याज में उल्लेखनीय राहत प्राप्त की गई है। यह योजना किसानों को वित्तीय पुनर्निर्माण का अवसर देती है और उन्हें पुन: मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक है। आगामी 30 जून से पूर्व ऋण की अवधिपार राशि का कम से कम 25 प्रतिशत जमा कर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के किसानों को उल्लेखनीय राहत दी गई है। मथानियां तिंवरी के अमानाराम को 3,41,554 रूपए, भीयासर आउ के पूनमचंद को 2,23,812, बावड़ी के देवीसिंह को 2,02,665, आमला फलौदी के ब्रह्मदेव को 1,65,210, सेखाला के रेवन्तसिंह को 1,33,845, दलपत नगर शेरगढ़ के धारूराम को 1,07,850, बाराकल्ला ओसियां निवासी श्यामलाल को 1,06,500 रूपए की राहत प्रदान की गई है। इस सभी ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार प्रकट किया है।

बढ़ता निराश्रित गोवंश तथा प्लास्टिक का उपयोग गंभीर चुनौती

यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन कड़वा सच यही है कि राजस्थान में निराश्रित गोवंश की भलाई के दावों और हकीकत के बीच बड़ा अंतर है। हाल ही सामने आए एक अध्ययन के अनुसार राजधानी जयपुर में 60 प्रतिशत से अधिक निराश्रित गायों की मृत्यु का कारण प्लास्टिक का सेवन है। पूरे प्रदेश का हाल भी कमोबेश ऐसा ही है। प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग और निराश्रित गोवंश की लगातार बढ़ती संया सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक चुनौती बन चुके हैं। निराश्रित गोवंश जहां खेतों में घुसकर फसलों को नष्ट कर देते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, वहीं प्लास्टिक वर्षों तक नष्ट नहीं होता, जिससे मिट्टी और जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं।प्रदेश में इन दोनों ही चुनौतियों से निपटने के प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कहने को पशु आश्रय स्थल जनसहभागिता योजना के तहत जिन ग्राम पंचायतों में गोशाला नहीं है, वहां गोशाला अथवा पशु आश्रय स्थल खोलने का प्रावधान किया गया है, लेकिन कितनी गोशालाएं खुली, यह किसी से छिपा नहीं है। इसी तरह, बजट 2025 में पात्र गोशालाओं में पल रहे गोवंश के चारे-पानी की व्यवस्था के लिए गोशालाओं की अनुदान राशि में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इसके बावजूद निराश्रित गोवंश की संया लगातार बढ़ रही है। इधर, प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने में भी सफलता नहीं मिल पा रही हैं। इसके पीछे कई चुनौतियां हैं। प्लास्टिक का व्यापक उपयोग, सस्ते विकल्पों का अभाव आदि इस दिशा में गंभीर बाधाएं बने हुए हैं। प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन और रीसाइक्लिंग की व्यवस्था भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। बहरहाल, प्लास्टिक पर प्रतिबंध को गंभीरता से लागू करना तथा उल्लंघन पर सत जुर्माना सुनिश्चित करना समय की मांग की है। प्लास्टिक के विकल्पों को भी प्रोत्साहित करना होगा। निराश्रित गोवंश के लिए चारे-पानी की व्यवस्था में सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देना होगा और अधिक संया में सुरक्षित एवं संसाधनयुक्त गोशालाएं विकसित करनी होंगी। आमजन को भी पशु-कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनना होगा।

मानसून के जल्दी आने के नुकसान ज्यादा

जल्दी मॉनसून के कुछ वैश्विक कारक भी हैं. अल नीनो की तरह इनमें से एक मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन हिंद महासागर में बादलों और बारिश को प्रभावित करने वाली एक वैश्विक मौसमी घटना है. इसके अनुकूल चरण मॉनसूनी हवाओं के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना सकते हैं और मॉनसून को जल्दी ला सकते हैं.

कहते हैं कि जब जेठ तपता है, तब आषाढ़ बरसता है और सावन-भादों में झड़ी लगती है. इस साल जब नौतपा में देश को खूब गर्म होना था, तब बरसात की ऐसी झड़ी लगी, जैसे सावन हो. मौसम वैज्ञानिक विचार करते रहे कि यह मॉनसून-पूर्व बरसात है, लेकिन चुपके से कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में मॉनसून की बदलियां जल्दी ही धमक गयीं. हमारे देश का अर्थतंत्र और सामाजिक तानाबाना मॉनसून पर निर्भर है. जल्दी बरसात ने भले ही ताप के प्रभाव को कम कर दिया हो, लेकिन यदि जलवायु परिवर्तन के कारण इस तरह मॉनसून अनियमित होता रहा, तो देश के समीकरण गड़बड़ा जायेंगे. इस बार केरल में मॉनसून आठ दिन पहले 24 मई को ही आ गया, जबकि इसकी सामान्य आगमन तिथि एक जून है. मुंबई और कर्नाटक में भी मॉनसून समय से काफी पहले आ गया. मुंबई में मॉनसून की सामान्य आगमन तिथि 11 जून है, जबकि यह 26 मई को आ गया. कर्नाटक में एक से पांच जून की सामान्य तिथि की तुलना में बादलों का डेरा 26 मई को ही आ गया. अरबी शब्द 'मौसिम' का अर्थ होता है मौसम और इसी से बना है मॉनसून. अरब सागर में बहने वाली मौसमी हवाओं के लिए अरबी मल्लाह इस शब्द का इस्तेमाल करते थे. अपने यहां खेती-हरियाली और साल भर के जल की जुगाड़ मॉनसूम की इसी बरसात पर निर्भर है. जलवायु परिवर्तन का गहरा असर, जाहिर है, भारत में अब दिखने लगा है. इसके साथ ही ठंड के दिनों में अलनीनो और दीगर मौसम में ला नीना का असर हमारे मॉनसून-तंत्र

को प्रभावित कर रहा है. इस साल बहुत पहले और भयंकर बरसात का प्रमुख कारण समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि माना जा रहा है. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सतह का तापमान सामान्य से अधिक हो जाने से मॉनसून जल्दी शुरू हो सकता है. ग्लोबल वार्मिंग के कारण महासागरों का तापमान बढ़ रहा है, जिससे वायुमंडल में नमी बढ़ती है और बादल जल्दी बनते हैं. जैसे-जैसे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है, वातावरण में नमी की मात्रा भी बढ़ती है. अनुमान है कि प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर वातावरण में छह से आठ प्रतिशत नमी बढ़ जाती है. यह बढ़ी हुई नमी मॉनसून की हवाओं को तेजी से सक्रिय कर सकती है. जल्दी मॉनसून के कुछ वैश्विक कारक भी हैं. अल नीनो की तरह इनमें से एक मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन हिंद महासागर में बादलों और बारिश को प्रभावित करने वाली एक वैश्विक मौसमी घटना है. इसके अनुकूल चरण मॉनसूनी हवाओं के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना सकते हैं और मॉनसून को जल्दी ला सकते हैं. एक अन्य कारण वैश्विक कारक सोमाली जेट है. मॉरीशस और मेडागास्कर के पास से निकलने वाली एक प्रमुख निम्न-स्तरीय पवन धारा पिछले महीने तीव्र हो गयी. यह जेट अरब सागर के पार केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र सहित भारत के पश्चिमी तट पर नमी से भरी हवा पहुंचाता है. इस साल इसकी असामान्य ताकत मानवजनित प्रभावों के कारण प्रतीत होती है. इंडियन ओशन डायपोल (आइओडी) का पॉजिटिव होना भी एक बड़ा कारण है. यह अरब सागर में नमी के जमाव को बढ़ाता है, जिससे मॉनसूनी हवाएं तेज होती हैं और जो मॉनसून के जल्दी आने का कारण भी बन सकता है. जल्दी बरसात आने से महानगरों की तैयारी अधूरी रही और चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरू और दिल्ली जैसे शहर डूब-से गये. लेकिन सबसे बड़ा संकट तो किसान का है. किसानी आज भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. किसानों को अ सर मॉनसून के एक निश्चित समय पर आने की उम्मीद होती है. यदि यह जल्दी आ जाता है, तो वे खेत तैयार करने, बुवाई करने या सही फसल का चुनाव करने के लिए तैयार नहीं हो सकते. यदि बुवाई के बाद अचानक भारी बारिश होती है, तो कोमल पौधे (अंकुरित फसल) नष्ट हो सकते हैं या मिट्टी की ऊपरी परत कठोर हो सकती है, जिससे पौधों के बढ़ने में बाधा आती है. अगर कोई फसल पहले से ही पक चुकी है या कटाई के करीब है और मॉनसून जल्दी आ जाता है, तो भारी बारिश से फसलें खराब हो सकती हैं, उनमें फंगस लग सकता है या वे खेत में ही सड़ सकती हैं. कुछ फसलों को एक निश्चित शुष्क अवधि की जरूरत होती है और जल्दी मॉनसून से उनका सामान्य फसल चक्र बाधित हो सकता है. मई में हुई वर्षा से आम, अनार, संतरा, मीठा नींबू और स जियों और बाजरा तथा मक्का को नुकसान पहुंचा है. महाराष्ट्र में खासकर मराठवाड़ा और विदर्भ के उन किसानों को इस बारिश से परेशानी हुई है, जो आगामी खरीफ सीजन के लिए अपने खेत तैयार करने में जुटे थे.

मॉनसून भारत की सामाजिक-आर्थिक खुशहाली में एक महत्वपूर्ण कारक है. सामान्य मॉनसून से किसी भी प्रकार का विचलन दूरगामी परिणाम पैदा कर सकता है, जिसका असर कृषि, ग्रामीण आजीविका, समग्र अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिरता पर भी पड़ सकता है. जल्दी मॉनसून का आना मौसम के पैटर्न में एक व्यवधान का संकेत हो सकता है, जो कृषि से लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे तक कई क्षेत्रों में अनपेक्षित और नकारात्मक परिणाम पैदा कर सकता है.

– पंकज शुक्ल
यह लेखक के अपने विचार हैं

रेपो दर में कटौती से विकास को गति

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक अहम फैसला लेते हुए रेपो दर में 0.50 प्रतिशत की कटौती की है, जिससे यह अब 5.5 प्रतिशत पर आ गई है। साथ ही, बैंकों के लिए नकद आरक्षित अनुपात में भी 1 प्रतिशत की कटौती की गई है, जो अब 3 प्रतिशत रह गया है। इस फैसले को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के पांच में से छह सदस्यों का समर्थन मिला, जिससे वह साफहो गया कि आर्थिक वृद्धि को गति देने की दिशा में एकजुट सोच विकसित हो रही है। रेपो दर वह दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से अल्पकालिक ऋण लेते हैं। जब यह दर घटती है तो बैंकों के लिए फंड लेना सस्ता हो जाता है, और वे ग्राहकों को भी कम ब्याज दर पर ऋण देने लगते हैं। इससे न केवल लोगों की ईएमआई घटती है, बल्कि बाजार में खर्च करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। इस बार की कटौती से वह उम्मीद की जा रही है कि आम आदमी को होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन में राहत मिलेगी। सीआरआर वानी कैश रिजर्व रेश्यो वह राशि होती है, जिसे बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास सुरक्षित रखना होता है। सीआर आर घटाने से बैंकों के पास ज्यादा फंड उपलब्ध होते हैं, जिन्हें वे बाजार में लोन देने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आरबीआई का अनुमान है कि इस कदम से बैंकिंग प्रणाली में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी आएगी, जिससे कर्ज देने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब महंगाई दर में स्थिरता देखने को मिल रही है और अप्रैल 2025 में यह घटकर 3.16 प्रतिशत के स्तर पर आ गई, जो कि पिछले छह वर्षों का न्यूनतम स्तर है। आरबीआई को खुदरा मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत के आसपास बनाए रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है और फिलहाल यह लक्ष्य के भीतर बनी हुई है। यही कारण है कि आरबीआई को ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश मिली है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने

भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक अहम फैसला लेते हुए रेपो दर में 0.50 प्रतिशत की कटौती की है, जिससे यह अब 5.5 प्रतिशत पर आ गई है। साथ ही, बैंकों के लिए नकद आरक्षित अनुपात में भी 1 प्रतिशत की कटौती की गई है।

स्पष्ट किया कि यह निर्णय केवल मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि वर्तमान वैश्विक और घरेलू आर्थिक हालात को देखते हुए लिया गया है। वैश्विक स्तर पर मंदी और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं की वजह से भारत जैसे विकासशील देशों को अपने घरेलू मांग पर अधिक ध्यान केंद्रित करना जरूरी हो गया है। रेपो दर और सीआरआर में कटौती इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे घरेलू खपत और निवेश को बढ़ावा मिल सकता है।

कम ब्याज दरों का सीधा असर रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एमएसएमई सेक्टर पर पड़ेगा। इन क्षेत्रों में मांग काफी हद तक सस्ते ऋण पर निर्भर होती है। जैसे-जैसे ऋण सस्ता होगा, वैसे-वैसे लोग घर खरीदने, वाहन लेने या छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिक प्रेरित होंगे। इससे बाजार में नकदी प्रवाह बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी बनेंगे। सरकार पहले से ही बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ा रही है और अगर इस मौद्रिक नीति का फायदा निवेश और खपत के रूप में सामने आता है, तो आर्थिक विकास दर को 6.5 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुंचाना मुमकिन होगा। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान इसी स्तर पर बरकरार रखा है। आरबीआई का रुख अब तटस्थ हो गया है, जिसका अर्थ है कि भविष्य में वह स्थिति के अनुसार ब्याज दरों में कटौती या बढ़ोतरी का लचीलापन बनाए रखेगा। इसका यह भी संकेत है कि रेपो दर में अब ज्यादा कटौती की गुंजाइश सीमित है और आगे के निर्णय आर्थिक संकेतकों पर निर्भर करेंगे। यदि बैंक अतिरिक्त नकदी को सुरक्षित निवेशों में रखने की बजाय कर्ज देने में लगाएं, तो इसका लाभ उपभोक्ताओं और उद्यमों तक पहुंचेगा। साथ ही, उपभोक्ताओं के मन में आर्थिक स्थिरता और आय को लेकर भरोसा बना रहना जरूरी है, ताकि वे नया खर्च या निवेश करने का जोखिम उठाएं। इसका एक बड़ा असर यह भी हो सकता है कि भारत वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन सके। जब ब्याज दरें नियंत्रित हों और आर्थिक नीतियां विकास को समर्थन देती हों, तो यह बाजार में स्थायित्व और संभावनाएं पैदा करता है। इससे विदेशी निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता है, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए सकारात्मक संकेत है। कुल मिलाकर, रेपो दर और सीआरआर में कटौती एक रणनीतिक और समयानुकूल कदम है, जो महंगाई नियंत्रण के साथ-साथ आर्थिक वृद्धि को भी संतुलित करने की दिशा में उठाया गया है। यह नीति आम लोगों के जीवन को भी छूती है और व्यापक आर्थिक ढांचे को भी मजबूती देती है।

– देवेन्द्रराज सुथार
यह लेखक के अपने विचार हैं

सफलता की कहानी....

व्यवसाय विविधीकरण का नया अध्याय लिख रही

मालपुर वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

उदयपुर । गांव-गांव में फैली वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियां प्रदेश के विकास का नया अध्याय लिख रही हैं । यह समितियां ना केवल किसानों और पशुपालकों के जीवन को नई दिशा दे रही हैं, बल्कि गांवों में आवश्यक सुविधा की पूर्ति में अपना योगदान दे रही हैं सलूम्बर जिले की मालपुर वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति ने इस दिशा में दो कदम आगे बढ़ाते हुए सहकारिता क्षेत्र में व्यवसाय विविधिकरण की मिशाल कायम की हैं वर्ष 2014 से स्थापित हुई, मालपुर वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति ने आज क्षेत्र के विकास का नया आयाम दिया हैं । यह समिति वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र सहित अन्य कई सेवाएं संचालित कर रही हैं । जिनसे बड़ी संख्या में आमजन और किसान लाभांवित हो रहें हैं, यह समिति अपने प्राथमिक कार्य जीरो फिसदी पर ऋण, उत्तम किश्म के खाद-बीज एवं किटनाशक तथा उपभोक्ता को उच्च गुणवत्ता वस्तुएं उपलब्ध कराने का दायित्व निर्वहन कर रही हैं । आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता वित्तीय समावेशन को पूरी तरह साकार करने की ओर अग्रसर यह समिति मिनी सहकारी बैंक का कार्य भी संपादित कर रही हैं । जिसने बहुत कम सालों में ग्रामीणों का विश्वास जीता हैं, वर्तमान में इस समिति की ओर से संचालित मिनी सहकारी बैंक वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान टर्नओवर 36 लाख रुपए रहा हैं, जो इसके मिनी बैंक की कार्यकुशलता की परिचायक हैं, इतना ही नहीं, समिति प्रति वर्ष करीब 2 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त योजना के तहत ऋण वितरण का कार्य भी करती हैं । समिति के व्यवस्थापक नारायण लाल पटेल ने बताया कि मिनी बैंक में 4957 बचत खाते संचालित हैं, उल्लेखनीय हैं कि मालपुर वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति ने अपना दायरा बढ़ाते हुए व्यवसाय विविधिकरण को प्रोत्साहन देकर सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी बखूबी किया हैं । समिति द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही हैं, इतना ही नहीं समिति द्वारा तीन उचित मूल्य की दूकानों का संचालन भी किया जा रहा हैं । इसके अलावा समिति द्वारा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के जरिए समस्त प्रकार की खाद-बीज एवं किटनाशक भी यथोचित मुहैया कराएं जा रहें हैं । जिनमें बुवाई के समय किसानों को डीएपी, यूरिया, संगल सुपर फास्फेट, एनपीके आदि प्रकार की खाद अपने समिति मुख्यालय पर सहज रुप से प्राप्त हो जाती हैं । इसी को ध्यान में रखते हुए समिति ने भण्डार व्यवस्था पर भी काफी जोर दिया हैं । आज यहां पैक्स एज.एम.एससी. योजनान्तर्गत 500 मै. टन क्षमता का गोदाम बना हुआ हैं, साथ ही कार्यालय भवन और तीन दुकान भी मौजूद हैं ।

फैक्ट फाइल

समिति का नाम व पंजीयन मालपुर ग्राम सेवा सहकारी, जिला - सलूम्बर, **पंजीयन** - 2014

मुख्य कार्य - उर्वरक केंद्र, पीडीएस, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद, मिनी सहकारी बैंक संचालन

कुल ऋण वितरण - करीब 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष

मिनी बैंक की अमानत राशि करीब 35.90 लाख रुपए

11 साल पहले ही बनी समिति

किसी भी संस्थान के अनवरत रुप से सफल संचालन के लिए आवश्यक हैं, उसकी आय का नियमित स्रोत और इसके लिए आवश्यक हैं कुशल वित्तीय प्रबंधन । इस सहकारी समिति ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक लगातार मुनाफा कमाकर अपनी सुदृढ़ प्रबंध व्यवस्था को साबित किया हैं ।

सफल संचालन के पीछे यह हैं राज

जनजाति बाहुल्य क्षेत्र की मालपुर वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति ने संचालक मण्डल सदस्यों एवं समिति अध्यक्ष एवं व्यवस्थापक के संयुक्त प्रयासों, सहकारिता अधिकारियों के मार्गदर्शन और कुछ नया करने की ललक के कारण से मालपुर सहकारी समिति ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई हैं, एक ही परिसर में बहुआयामी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा हैं । समिति जिले की क्रेफिकार्ड योजनान्तर्गत चयनित हैं । इस सहकारी समिति ने केंद्र सरकार की पैक्स को डिजीटल और पारदर्शी बनाने की पैक्स कंप्यूटराईजेशन परियोजना के कार्य को भी जिले में अग्रणी रुप से पूर्ण किया हैं, वर्तमान में समिति का अधिकतर कार्य ऑनलाइन ही किया जाता हैं ।

घर बैठे मारवाड़ का मित्र मंगाने के लिए भर कर भेजें

सदस्यता फॉर्म

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक मारवाड़ आंचल का प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र हैं । समाचार पत्र में कृषि पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम खबरों का प्रकाशन कर पाठकों तक अखबार की प्रति प्रेषण कर रहा है। मारवाड़ का मित्र समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर विशेषांक का प्रकाशन भी करता है तथा अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजता है । अतः मुझे / हमें भी अंग्राकित पते पर मारवाड़ का मित्र समाचार पत्र की प्रति डाक द्वारा भेजें ।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 500/- ☐ दो वर्ष रु. 1000/- ☐ तीन वर्ष रु. 1500/- ☐ छह वर्ष रु. 3000/-

डाक से नियमित रूप से इस पते पर मारवाड़ का मित्र भेजने के लिए DD / मनीआर्डर मारवाड़ का मित्र के नाम भेज रहा हूं ।

नाम / संस्था का नाम.....
ग्राम..... पोस्ट.....
तहसील..... जिला.....
फोन..... पिन कोड.....
राशि (रुपए) ..... बैंक का नाम.....

अगर आप किसी कारण से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजें. अगर आप सीधे बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो Marwadkamitra@gmail.com पर अपना पूरा नाम, फोन नंबर, भुगतान की राशि और Transaction id हमें मेल करें ताकि हम आपका व्यक्तिगत तौर पर आभार प्रकट कर सकें.

Bank Account Details :
Name: Marwad ka Mitra
A/C No.: 11134027554
IFSC Code: RMGB0000134
Google / Phonepay 9602473302

सदस्यता हेतु → मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र
Mo. 9602473302, Marwadkamitra.in
संपादकीय/व्यवस्थापक कार्यालय - वैष्णव फार्म परावा, तहसील-चितलवाना जिला-जालोर 343041

अलवर जिले में चल रहा सहकारी समितियों कर्मचारियों का आंदोलन समाप्त

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

अलवर । जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारियों द्वारा राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन जिला यूनिट अलवर के बैनर तले पिछले 13 दिनों से पैक्स के दैनिक कार्यो का बहिष्कार चल रहा था, जिसे समाप्त कर दिया गया हैं । यूनियन के जिला अध्यक्ष देवेन्द्र कुमार सैदावत और संघर्ष समिति संयोजक ओमप्रकाश शर्मा सहित 21 सदस्यों से अलवर केंद्रीय सहकारी बैंक प्रधान कार्यालय में हुई वार्ता के उपरांत कल सीसीबी द्वारा पैक्स कर्मियों की प्रमुख मांगों के निराकरण के लिए पत्र जारी किया गया, जिसके पश्चात यूनियन की ओर से उसमें सुझाव और संशोधन की मांग उठाने पर सीसीबी स्तर से सुझाव शामिल करने की सहमति बनने पर कार्य बहिष्कार समाप्त कर दिया गया हैं । गौरतलब हैं कि जिले में बैंक प्रशासक एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन प्रस्तुत करने के उपरांत यूनियन द्वारा 22 मई से ही कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया गया था ।

एरियर ब्याज का होगा भुगतान, बनी कमेटी

सीसीबी द्वारा एरियर ब्याज के संबंध में समस्त शाखा प्रबंधकों को सख्त निर्देश जारी कर साप्ताहिक एवं पाक्षिक रुप से प्रत्येक समिति के ऋण वसूली खाते का परीक्षण करने तथा एक ऋण खाते में बैलेन्स शून्य होने पर उस खाते की वसूली अन्य ऋण खाते में जमा करने के लिए पाबन्द किया गया है । साथ ही, यूनियन की एरियर ब्याज से संबंधित मांग में किसी प्रकार का वाद होने की स्थिती में प्रधान कार्यालय स्तर पर मुख्य प्रबन्धक की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें वरिष्ठ प्रबन्धक (आईटी), वरिष्ठ प्रबन्धक (ऋण) एवं प्रबन्धक (परिचालन) कमेटी के सदस्यों के अलावा यूनियन यूनिट अलवर द्वारा शाखावार नामित तीन-तीन व्यवस्थापकों को भी शामिल किया जाएगा । साथ ही कमेटी को 7 दिवस में वाद का निपटारा करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं ।

व्यवस्थापकों को मिलेगा 3 लाख का व्यक्तिगत ऋण

जिला यूनियन की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समिति स्तर से व्यवस्थापकों को व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए सीसीबी की ओर से पत्रावली तैयार कर बैंक प्रशासक एवं जिला कलेक्टर को अनुमोदन के लिए भेजी गई हैं, जिसके अनुसार 3 लाख तक ऋण व्यवस्थापकों को मिल सकेगा । साथ ही, पैक्स कंप्यूटराइजेशन में सहयोग करने वाली पैक्स में ऋण प्रतिबंध भी मुक्त किया जाएगा तथा 10 जून तक हिस्सा राशि समितियों को लौटाने और अल्पकालीन फसली ऋण में 2 फीसदी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया हैं ।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा यह सकारात्मक निर्णय

अलवर जिले में कार्य बहिष्कार के दौरान राजस्थान बहुउद्देशीय

सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमानसिंह राजावत द्वारा अलवर जिले के पैक्स कर्मियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए और अधिकारियों से सार्थक वार्ता भी की गई । उन्होने कहा कि जिला अध्यक्ष देवेन्द्र कुमार सैदावत और अलवर जिले के पैक्स कर्मियों की अपनी वाजिब मांगों के प्रति कर्मठता और जिले में एकता के चलते यह सकारात्मक निर्णय आया हैं ।

प्रदेश की शेष रही समस्त ग्राम पंचायतों में होगा नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप राज्य की शेष रही सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाना है। इन समितियों के गठन से राज्य में सहकारिता का नेटवर्क मजबूत होगा तथा अधिक लोगों तक सहकारिता की योजनाओं का लाभ पहुंच पाएगा। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन समितियों के गठन के कार्य में तेजी लाते हुए निर्धारित समय अवधि से पूर्व शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के प्रयास किये जाएं। श्रीमती राजपाल शासन सचिवालय स्थित कक्ष से वीसी के माध्यम से नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहीं थीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना के लिए सदस्य संख्या एवं न्यूनतम हिस्सा राशि के मापदण्डों में 50 प्रतिशत का शिथिलन दिया गया है, जिससे लक्ष्यों की प्राप्ति में आसानी होगी। नवीन समिति की स्थापना के लिए अब न्यूनतम सदस्य संख्या 150 एवं न्यूनतम हिस्सा राशि 1.50 लाख रुपये होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों में प्रस्ताव मिलने पर और भी शिथिलता दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि समिति गठन के मापदण्डों में दी गई शिथिलता से पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों एवं जिला परिषद् सीईओ आदि को भी पत्र लिखकर अवगत करवाया जाना चाहिए ताकि इसका अधिकाधिक लाभ मिल सके। साथ ही, समिति गठन के संबंध में आयोजित होने वाली बैठकों में संबंधित विभागों यथा- पंचायतीराज विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि समिति गठन के लिए प्रस्ताव तैयार होने के बाद उन्हें स्वीकृति के लिए अविलम्ब भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। चूंकि सभी शेष रही ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन होना है, अतः केवल माहवार निर्धारित लक्ष्यों पर फोकस करने की बजाय समानान्तर रूप से सभी शेष ग्राम पंचायतों में गठन की प्रक्रिया जारी रखें। बैठक में अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) श्री संदीप खण्डेलवाल एवं संयुक्त रजिस्ट्रार (आयोजना) श्री अनिल कुमार सहित सभी अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड) एवं जिला उप रजिस्ट्रार वीसी के माध्यम से शामिल हुए।

118 नवीन सहकारी समितियों का हो चुका गठन

श्रीमती राजपाल ने कहा कि एक अप्रेल के बाद राज्य में लगभग 118 नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन हो चुका है। इस कार्य में तेजी लाने के लिए सभी अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड) नियमित रूप से इसकी समीक्षा करें। जिन जिलों में समिति गठन के लक्ष्य अधिक हैं, उन जिलों के लिए अलग रणनीति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में खनन क्षेत्र अधिक है एवं किसानों की संख्या कम है, वहां महिला समितियां बनाई जा सकती हैं। साथ ही, आदिवासी क्षेत्रों में वन धन विकास केन्द्रों से समन्वय कर ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठित की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि मूल समिति से सदस्य पृथक् कर समिति बनाने की बजाय 150 नये सदस्यों को शामिल कर समिति गठन के प्रयास किये जाएं।

एमएसपी पर गेहूं की खरीद में भारतीय खाद्य निगम के अजमेर मंडल में हुई उल्लेखनीय प्रगति

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राज्य सरकार द्वारा एमएसपी पर गेहूं खरीद पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ सफलतापूर्वक की जा रही है। विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम के अजमेर मंडल में एफसीआई के अजमेर मंडल में अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, पाली एवं नागौर जिलें कवर होते हैं। इसके द्वारा इस वर्ष भी समस्त खरीद कार्य डिपो ऑनलाइन सिस्टम के ई-प्रोक्योरमेंट मोड्यूल के माध्यम से संचालित किया गया है। इस वर्ष एफसीआई अजमेर मंडल में संचालित 14 प्रमुख खरीद केंद्रों पर 18,890 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यह लक्ष्य निगम द्वारा खरीद केन्द्रों पर नियुक्त कर्मचारियों एवं किसानों के सक्रिय एवं उत्साहित भागीदारी के कारण समय से पहले पूर्ण हो जाने के पश्चात बढ़ाकर 33,890 मीट्रिक टन किया गया। इसे भी किसानों के सक्रिय सहयोग से समय से काफी पहले ही प्राप्त कर लिया गया। किसानों के उत्साह एवं एफसीआई के प्रभावी प्रबंधन के परिणामस्वरूप अब तक 48,191.7 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। यह प्रक्रिया अभी 30 जून तक जारी रहेगी। विशेष रूप से गुलाबपुरा (11,870.25 मीट्रिक टन), बिजयनगर (7,689.7 मीट्रिक टन), भीलवाड़ा (5,672.65 मीट्रिक टन), तखतगढ़ (4,011.85 मीट्रिक टन) और शाहपुरा (3,982 मीट्रिक टन) जैसे केंद्रों पर किसानों ने अपेक्षा से अधिक गेहूं विक्रय कर उल्लेखनीय सहभागिता निभाई है। सभी क्रियाशील खरीद केंद्रों पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पर्याप्त खरीद सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिले के बिजयनगर खरीद केंद्र पर प्रथम खरीद लक्ष्य 1600 से संशोधित खरीद लक्ष्य 4500 किया गया है।

कृषक नवीन तकनीके अपना कर वैज्ञानिक तरीके से करे खेती - विशाल

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। बसेडी, बस्सी झाझडा, गुढा कुमावतान क्षेत्रों का भ्रमण शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री राजन विशाल ने किया। उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा संचालित हाईटेक हॉर्टिकल्चर मॉडल कलस्टर बस्सी झाझडा में कृषक श्री अशोक निठारवाल के खेत पर स्थापित ग्रीन हाउस, फार्म पोण्ड , ड्रिप संयंत्र तथा अन्य उद्यानिकी गतिविधियों का निरीक्षण किया गया। शासन सचिव ने हाईटेक हॉर्टिकल्चर मॉडल कलस्टर बस्सी झाझडा क्षेत्र के चयनित कृषकों के साथ कृषक गोष्ठी का आयोजन कर किसानों से संवाद किया। कृषकों द्वारा उद्यानिकी विकास की गतिविधियों के लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने किसानों को ग्रीन हाउस में फसल विविधिकरण के तहत खीरा फसल के अलावा शिमला मिर्च, कटफ्लोवर (डचरोज), ब्लैकबेरी आदि फसले लेने हेतु प्रेरित किया गया ताकि किसानों को अधिक आर्थिक लाभ हो। गोष्ठी में किसानों से ग्रीन हाउस के आर्थिक मूल्यांकन पर भी चर्चा की गई। श्री विशाल ने कृषक श्री भैरूराम थाकण द्वारा गर्मी में बोये गये खीरें के खेत एवं कटफ्लोवर (डचरोज) के खेत का भ्रमण किया तथा कटफ्लोवर (डचरोज) के विपणन के बारे में किसानों को स्थानीय होटल व्यवसायियों से सम्पर्क कर विपणन किये जाने की सलाह दी। कृषक श्री भैरूराम थाकण, ग्राम बसेडी के खेत पर ही स्थापित पी.एम.कुसुम कम्पोनेन्ट 'बी' के तहत सौर उर्जा पम्प संयंत्र का निरीक्षण किया। शासन सचिव द्वारा सभी किसानों को संरक्षित खेती के तहत उत्तरोत्तर वृद्धि किये जाने हेतु उद्यानिकी की नवीनतम तकनीकी अपनाते हुये वैज्ञानिक तरीके से खेती किये जाने हेतु प्रेरित किया गया। किसानों द्वारा डचरोज को लम्बे समय तक संरक्षित रखने हेतु कोल्ड स्टोरेज व रेफ्रीजरेटेड वैन पर अनुदान दिये जाने की मांग की गई। किसानों की मांग पर शासन सचिव ने अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनान्तर्गत कोल्ड स्टोरेज व रेफ्रीजरेटेड वैन पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। अतः कृषक इस हेतु आवेदन कर अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते है ताकि कृषकों को डचरोज के विपणन में कोई असुविधा न हो।

'सहकार से समृद्धि' की समीक्षा बैठक क्रियान्विति में पिछड़ रहे जिलों पर करें फोकस

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। 'सहकार से समृद्धि' के अंतर्गत राज्य में क्रियान्वित की जा रही पहलों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने कहा कि क्रियान्विति में पिछड़ रहे जिलों पर विशेष रूप से फोकस करते हुए उनसे प्रगति की नियमित रिपोर्ट ली जाए। उन्होने कहा कि वास्तविक डेटा एवं एनसीडी पोर्टल पर उपलब्ध डेटा में अंतर को दूर करने के लिए नई गठित पैक्स का अविलम्ब रजिस्ट्रेशन करते हुए उन्हें फंक्शनल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि गो-लाइव हो चुकी सभी पैक्स की ई-ऑडिट करवाई जाए। बैठक में अधिकारियों द्वारा बताया गया कि अब तक 5,154 पैक्स गो-लाइव हो चुकी है तथा 603 पैक्स की ऑनलाइन ऑडिट सम्पन्न हो चुकी है। प्रमुख शासन सचिव ने निष्क्रिय समितियों के अवसायन के कार्य में भी गति लाने के निर्देश दिए। भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप निष्क्रिय समितियों के अवसायन की प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न की जानी है। उन्होंने एनसीएफ एवं नैफेड के पोर्टल पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राप्त कर रहे एवं अल्पकालीन ऋण ले रहे किसानों का रजिस्ट्रेशन करवाने के भी निर्देश दिए, जिससे उन्हें उक्त पोर्टल से लाभ प्राप्त हो सके। बैठक में पैक्स का एफपीओ के रूप में संचालन, नेशनल को-ऑपरेटिव डाटाबेस, व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0, सहकार में सहकारिता, आरसीएस कार्यालयों एवं एआरडीबी के कम्प्यूटराइजेशन, एससीडीसी एवं एसएसी की बैठकों में लिए गए निर्णयों की पालना एवं सहकारिता मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों की पालना के संबंध में भी समीक्षा की गई।

सहकारी उपभोक्ता भंडार के उपहार सुपर मार्ट एवं श्री अन्न आऊटलेट का उद्घाटन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । अलवर जिला स्थित काला कुआं में सहकारी उपभोक्ता भंडार के उपहार सुपर मार्ट एवं श्री अन्न योजना के तहत मोटे अनाजों के आऊटलेट का उद्घाटन पर्यावरण एवं वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने किया । उन्होंने कहा कि श्रीअन्न (मिलेट) सदियों से राजस्थान की खाद्य संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। इनमें भरपूर पोषक तत्व होने के कारण ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीअन्न (मिलेट) को स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बताते हुए श्रीअन्न के भोजन में उपयोग पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा में श्री अन्न (मिलेट) के उत्पाद आमजन को आसानी से उपलब्ध करवाने एवं मोटे अनाजों को प्रचलन में लाने के उद्देश्य से हर जिले के प्रमुख स्थानों को चिन्हित कर मिलेट्स उत्पाद विक्रय केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा श्रीअन्न प्रसंस्करण एवं ब्रांडिंग को बढ़ावा देने एवं सहकारी संस्थाओं एवं स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी बढ़ाकर रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए निरन्तर सकारात्मक प्रयास कर रही है। इस दौरान मंत्री श्री शर्मा ने स्वंय श्रीअन्न के कुकीज, श्रीअन्न आटा और पिंक साल्ट खरीद कर श्रीअन्न को पोषक युक्त और स्वास्थवर्धक बताते हुए श्री अन्न को दैनिक आहार में शामिल करने की अपील की। अलवर सहकारी उपभोक्ता भंडार के प्रबंधक श्री प्रकाश नारायण झा ने बताया कि सुपर मार्ट में अन्न उत्पादों में बाजरा, ज्वार जैसे श्रीअन्न से बने बिस्किट, नमकीन, आटा, टोस्ट, दलिया, लड्डू, चिक्की सहित कई उत्पाद उचित दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही यहां किराना सामग्री, जनरल आइटम, होजरी, क्रॉकरी और स्टेशनरी सहित कई प्रकार की आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध रहेंगी। यहां मिलने वाली वस्तुओं पर 5 से 50 प्रतिशत तक की छूटी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सुपर मार्ट का संचालन प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा।इसके उपरान्त मंत्री श्री शर्मा ने अपने नियमित पौधा लगाने के संकल्प के तहत विवेकानन्द नगर सेक्टर 4 में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया

गांवों में आधार से जुड़ सकते हैं संपत्तियों के रिकार्ड

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली। स्वेच्छा और सहमति से ही सही, केंद्र सरकार ने गांवों में संपत्तियों के रिकॉर्ड को आधार से जोड़ने और मोबाइल नंबर अपडेट कराने की दिशा में काम शुरू किया है। ग्रामीण भूमि रिकार्ड के आधुनिकीकरण और डिजिटाइजेशन के अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने जमीन के अधिकार के मामले में सभी भू स्वामियों और अंशधारकों के आधार को रिकॉर्ड से जोड़ने को महत्वपूर्ण माना है। इसी तरह मोबाइल नंबर और भू स्वामियों के पते को भी इसमें अपडेट करने पर जोर दिया गया है। आधार प्रमाणीकरण भले ही अनिवार्य नहीं है, लेकिन इससे जमीन के रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। इसी संदर्भ में सरकार ने

राज्यों से कहा है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण और डिजिटाइजेशन का काम पूरा करें जिससे वे सटीक और अद्यतन हों। इसी से सरकारी योजनाओं और बैंकिंग सेक्टर से उन्हें किसी अवरोध के बिना सुगम तरीके से जोड़ा जा सकेगा। इस साल बजट और गत वर्ष अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकारों की ओर से व्यापक भूमि सुधार में सहायता देने की घोषणा की थी। इसके लिए नेशनल जियोस्पैटियल मिशन का एलान किया गया था। सरकार की योजना पीएम गतिशक्ति का इस्तेमाल करते हुए इस मिशन के जरिये गांवों में जमीन के सभी रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण करने और शहरी नियोजन की दिशा तय करने की है। वित्त मंत्रालय ने इससे संबंधित जो योजना ग्रामीण विकास और आवास व शहरी कार्य मंत्रालय के साथ-साथ राज्य सरकारों के साथ साझा की है, उसके अनुसार गांवों में जमीन के रिकॉर्ड को लेकर बड़े पैमाने पर सुधार किए जाने हैं। उदाहरण के लिए मौजूदा स्वामित्व के आधार पर सभी लैंड पार्सल का उपवर्गीकरण, जिससे भूमि रिकार्ड के माध्यम से कब्जे, स्वामित्व और इस्तेमाल की तस्वीर एकदम साफ हो सके तथा सभी नक्शों के सत्यापन के लिए फिर से सर्वे। दूसरे चरण में सभी भूमि के लिए विशिष्ट पहचान संख्या (भू-आधार) जारी करना अनिवार्य है। इसके साथ ही सरकार ने इस पर भी जोर दिया है कि जमीन के रिकार्ड और नक्शों को लेकर जो विभिन्नताएं और विसंगतियां हैं, उन्हें प्राथमिकता दूर किया जाए। इनके इतने ज्यादा प्रारूप हैं कि कोई भी उन्हें आसानी से समझ नहीं सकता। यहां तक कि उनके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द, उनके अर्थ और नापने की इकाई में व्यापक अंतर है। यह अंतर अलग-अलग राज्यों में तो है ही, किसी एक राज्य के भीतर भी तमाम विसंगतियां और अंतर नजर आते हैं। वित्त मंत्रालय ने गांवों में जमीन के रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण और डिजिटाइजेशन के लिए राज्यों को चरणबद्ध तरीके से 2700 करोड़ रुपये की सहायता देने का प्रस्ताव दिया है। इसमें जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने का काम भी शामिल है।

किसानों को उच्च गुणवत्तायुक्त बीज एवं उर्वरक उपलब्ध कराना ही सरकार का प्रमुख ध्येय

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त खाद, बीज एवं उर्वरक उपलब्ध कराना ही सरकार का प्रमुख ध्येय हैं इसके लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोडी लाल मीणा ने बताया कि उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और अमानक उर्वरकों व बीजों पर अंकुश लागाने के लिए कृषि विभाग द्वारा समय-समय पर विशेष गुण नियंत्रण अभियान चलाये जाते हैं। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री सोमवार को शासन सचिवालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने बताया कि विनिर्माताओं और निर्माताओं के निरीक्षण के दौरान अनियमित्ता पाये जाने पर कृषि आदानों से संबंधित नियमों, अधिनियमों, उर्वरकर नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत बिक्री पर रोक, जब्ती, लाइसेंस निलंबन या निरस्तिकरण जैसी कार्यवाही की जा रही हैं। कृषि मंत्री ने बैठक में निर्देशित किया कि कृषि विभाग से संबंधित जन समस्याओं के निराकरण हेतु एक पृथक कॉल सेंटर की व्यवस्था करें। जहां पर जन शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जा सकेगा ।

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र
सांचौर (जिला-जालोर) रविवार, 15 जून 2025
4
RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136
Post Reg No. R.J./SRO/9657/2023-25

रबी सीजन में भी ऐसी ही समस्या को लेकर जालोर, डूंगरपुर और बांरा सीसीबी प्रबंध निदेशक द्वारा पत्र लिखने के बावजूद व्यवस्था जस की तस

एफआईजी पोर्टल सर्वर समस्या के मामले में मूकदर्शक बना सहकारिता विभाग

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, सहकारिता विभाग के गर्म-मिज़ाज हेड की पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना को पूर्ण करने की ललक और राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की चुप्पी के कारण ग्राम सेवा सहकारी समितियों में किसानों और व्यवस्थापकों के मध्य लड़ाई होने जैसी स्थिती बनती नजर आ रही हैं । एफआईजी पोर्टल की सर्वर समस्या के कारण किसानों को यह भीषण गर्मी सहन नहीं हो पा रही हैं और किसान पिछले दो सप्ताह से परेशान हैं । वही एफआईजी पोर्टल की नाकामी को लेकर अलवर, जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक को सर्वर समस्या के समाधान के लिए पत्र लिखा गया हैं। जिसके मुताबिक सेवा अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है, कृपया लेन-देन संसाधित होने तक प्रतीक्षा करें, सॉकेट अनुपलब्ध है, लेन-देन समय समाप्त हो गया है, जैसी समस्याएं फसली ऋण वितरण के दौरान आ रही हैं । गौरतलब हैं कि पिछली बार रबी सीजन में भी ऐसी ही समस्या को लेकर जालोर, डूंगरपुर और बांरा सीसीबी प्रबंध निदेशक द्वारा पत्र लिखने के बावजूद व्यवस्था जस की तस बनी हुई हैं ।

सहकारिता मंत्री का नहीं ध्यान, नेता प्रतिपक्ष ने लिखा पत्र और अपेक्स बैंक ने कहा रात्रि 9 बजे तक करों कार्य

क्या सहकारिता मंत्री का नहीं है ध्यान

प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से खरीफ सीजन में 12 हजार करोड़ का ऋण वितरण का लक्ष्य आंवटन किया हुआ हैं, वही फसली ऋण वितरण के लिए एक मात्र विकल्प एफआईजी पोर्टल में सर्वर समस्या आ रही हैं । क्या इसकी जानकारी विभाग के मुखिया यानी सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक को नहीं है. यह एक बड़ा सवाल है. मारवाड़ का मित्र ने इस मामले में मंत्री गौतम कुमार दक से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई ।

नेता प्रतिपक्ष ने मंत्री को लिखा पत्र

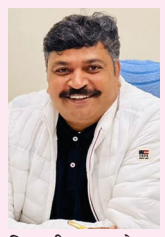

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के ऋण वितरण एवं वसूली पोर्टल एफआईजी नहीं चलने के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक को पत्र लिखा गया । जिसमें बताया गया कि वर्तमान में खरीफ ऋण वितरण के कार्य की अधिकता होने के कारण एफआईजी पोर्टल काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ऋण जमा एवं वसूली का कार्य नहीं हो पा रहा है। इस भीषण गर्मी में किसान सुबह से शाम तक पोर्टल शुरू होने का इंतजार कर वापस लौट जाते हैं। इसके अलावा, पत्र में लिखा गया किप्रदेश के किसान इस विकट समस्या को लेकर हैरान और परेशान हैं।

हर सीसीबी में डेढ़ घंटे का आउन टाइम रहेगा

एफआईजी सर्वर की समस्या का मुद्दा जोर पकड़ते ही राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा एक बार फिर अपना पल्ला झाड़ते हुए एक बेनामी एडवाइजरी व्हाट्सएप ग्रुपों पर जारी की गई हैं, जिसमें बताया कि हर सीसीबी में डेढ़ घंटे का डाउन टाइम रहेगा । प्रदेश की प्रत्येक 29 सीसीबी में 10.30 बजे से लेकर 3 बजे तक के लिए अलग-अलग डेढ़ घंटे का डाउन टाइम रहने की एडवाइजरी जारी हुई हैं । हालांकि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की इस बेनामी एडवाइजरी में पैक्स से लेकर सीसीबी प्रबंधन को रात्रि 9 बजे तक कार्य करने का सुझाव लिखा गया हैं, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड की ओर से सहकारी बैंकों में काउंटर संचालन में जारी दिशा-निर्देशों के विपरित माना जा रहा हैं ।

अभी चेक करवाते हैं

राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के एफआईजी पोर्टल की समस्या के मामले को लेकर जब राजस्थान राज्य सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक संजय पाठक से मारवाड़ का मित्र ने फोन पर बात की तो उन्होने कहा कि एफआईजी पर एकदम से कभी लगातार ज्यादा प्रेशर आ जाता हैं, तो पोर्टल स्लो हो जाता हैं, अभी चेक करवाते हैं।

अपग्रेडेशन की जरुरत

सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा द्वारा एफआईजी पोर्टल में पैक्स स्तर पर आ रही दैनिक समस्याओं और कठिनाईयों की वजह से किसानों, पैक्स कर्मचारियों एवं बैंक प्रबंधन को होनी परेशानी पर चिंता व्यक्त करते हुए राजस्थान राज्य सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर एफआईजी पोर्टल का अपग्रेडेशन करने की उठाई मांग

सहकारिता मंत्री को दिया ज्ञापन

राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमानसिंह राजावत ने बताया कि एफआईजी सर्वर समस्या संपूर्ण राजस्थान में बनी हुई हैं, अपेक्स बैंक में बैठे अधिकारी को इस समस्या की सारी जानकारी होने के बावजूद वह इस समस्या को दुरुस्त करने की पहल नहीं कर रहें हैं । यूनियन महामंत्री दैवेन्द्र कुमार सैदावत द्वारा सहकारिता मंत्री जी से मुलाकात कर इस समस्या को लेकर परिवेदना प्रस्तुत की।

एक्सपर्ट व्यू

एफआईजी पोर्टल में आ रही सर्वर समस्या को लेकर सहकारी एक्सपर्टो एवं तकनीकी जानकारों का कहना हैं कि एफआईजी पोर्टल में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक स्तर से इसकी क्षमता इतनी ही रहेगी, जो बढ़ानी थी, वो बढ़ाई जा चुकी हैं, इस प्रकरण में किसी प्रकार की सहुलियत मिलने की आंशका तक नहीं हैं । क्योकि आनन-फानन में लागू किए गए इस पोर्टल में शुरु से ही तकनीकी खामियां दुरुस्त नहीं की गई ।

विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की समीक्षा बैठक आयोजित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली । स्थित सहकारिता मंत्रालय में सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की समीक्षा बैठक केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसको संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विज़न को साकार करने की दिशा में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि भारत में आर्थिक प्रगति को मापने के दो प्रमुख मापदंड हैं— सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार सृजन। अन्न भंडारण योजना इन दोनों पहलुओं को सशक्त बनाने का माध्यम है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की आमदनी बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण रोजगार के अवसरों को सृजित करना है। श्री शाह ने कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत ऋण अवधि के विस्तार से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।

सहकारिता विभाग ने जारी की मानक संचालन प्रक्रिया

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत राज्य में निर्मित किये जा रहे गोदामों को अब किराये पर दिया जा सकेगा। सहकारिता विभाग द्वारा इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। गोदामों को किराये पर दिए जाने से पैक्स को नियमित आय होगी और उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराने तथा पैक्स की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 'सहकार से समृद्धि' कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में वृहद् स्तर पर गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही वित्तीय सहायता से ये गोदाम निर्मित किये जा रहे हैं। श्रीमती राजपाल ने बताया कि समिति द्वारा गोदाम किराये पर देने के लिए पूरे वर्ष का एक कैलेण्डर तैयार किया जाएगा। साथ ही उन्होने बताया कि नैफेड तथा एनसीसीएफ द्वारा इन गोदामों को किराये पर लिए जाने के लिए आश्वस्त किया गया है।

20 जून तक ग्राहक जोड़ो पखवाड़े का आयोजन

केंद्रीय सहकारी बैंक ने किया ग्राहक जोड़ो अभियान का शुभारंभ

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

उदयपुर । सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने तथा सहकारिता का लाभ जन-जन तक पहुंचाने की दृष्टि से वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। इस दौरान सहकारी बैंकों की वित्तीय सक्षमता बढ़ाने की दृष्टि से इनकी जमाओं में वृद्धि करने के लिए उदयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा ग्राहक जोड़ो अभियान का शुभारंभ किया गया । इसके प्रथम चरण में 5 जून से 20 जून तक ग्राहक जोड़ो पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा, जिसके पोस्टर का आज प्रतापनगर स्थित प्रधान कार्यालय में श्रीमती गुंजन चौबे अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खंड उदयपुर, आशुतोष भट्ट क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी, नीरज यादव डीडीएम नाबार्ड उदयपुर, सीसीबी प्रबंध निदेशक डॉ मेहजबीन बानों, लोकेश जोशी उप रजिस्ट्रार, डॉ प्रमोद कुमार महाप्रबंधक उदयपुर भंडार तथा सीसीबी के मुख्य

ग्राहक जोड़ो अभियान के पोस्टर का विमोचन करते

प्रबंधक श्री के.एल. शर्मा द्वारा विमोचन किया गया । इस दौरान अभियान की जानकारी प्रदान करते हुए प्रबंध निदेशक ने बताया कि अमानतों की स्थिति बैंक की आर्थिक सुदृढता एवं ग्राहको के विश्वास का परिमापक है, तथा बैंक व्यवसाय में ऋण वितरण के लिए तरल संसाधनों की पूर्ति भी ग्राहको से प्राप्त अमानतो से की जाती है । उन्होने अभियान के दौरान बैंक क्षेत्र की सभी शाखाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शाखाओं में अधिकाधिक व्यक्तिगत अमानत खातें खुलवाए जाने, खाली पडे लॉकर्स का आंवटन करने, विभिन्न सरकारी, सहकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से जमाऐ प्राप्त करने के लक्ष्य आंवटित किए है। साथ ही 'म्हारो खातो म्हारो बैंक' अभियान की क्रियान्विति के अन्तर्गत डेयरी एवं क्रेडिट को-ऑपरेटिव समितियों से भी जमाऐ प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा शाखा प्रबंधको को अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और गणमान्य नागरिकों व प्रमुख व्यवसायियों को पत्र लिख कर अमानत खाते खोलने के लिए प्रेरित करने के लिए निर्देशित किया गया है ।

समृद्धि के दौर में 2000 से ज्यादा ग्राम सेवा सहकारी समितियां "बेघर"

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

***जयपुर ।** सहकारिता विभाग ने केवल ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाने पर फोकस किया । लेकिन इन समितियों में मानव संसाधन और स्थाई कार्यालय देने के मामले में हवा-हवाई आदेश जारी कर इतिश्री करने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ी हैं । जिससे आज प्रदेश की 2000 से ज्यादा ग्राम सेवा सहकारी समितियां इस समृद्धि के दौर में बेघर हैं । इनके पास अपना कार्यालय भवन और गोदाम तक नहीं हैं । इससे न केवल समितियों के संचालन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि किराया चुकाने से उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही है। इन समितियों के पास किसानों को ऋण और खाद बीज देने सहित कई महत्वपूर्ण काम होते हैं । दरअसल, प्रदेश में 7 हजार से ज्यादा सहकारी समितियां संचालित हैं। इनमें से 2 हजार से भी ज्यादा समितियों के पास खुद के भवन और गोदाम नहीं हैं। सरकार से पर्याप्त सहायता नहीं मिलने से ग्राम सहकारी समितियों को अपने भवन और गोदाम बनाने में परेशानी हो रही है। कई जगहों पर पंचायत से जमीन नहीं मिलने के कारण भी भवन और गोदाम बनाए जाने में समस्या आ रही है। मगर प्रदेश में नव गठित जिलों को छोड़ दें तो पूर्व के 33 जिलों में से 29 जिलों के कार्यक्षेत्र की सैकड़ों समितियों के पास अपने भवन और गोदाम नहीं हैं। इनमें जयपुर, अजमेर, जोधपुर, सीकर, बीकानेर, अलवर, उदयपुर सहित तमाम बड़े जिले शामिल हैं। सर्वाधिक अलवर जिले में समितियों के पास भवन गोदाम नहीं हैं। इसके अलावा बाड़मेर, भरतपुर, जयपुर, झुंझुनूं, नागौर, सवाई माधोपुर और उदयपुर जिले में तो आधा दर्जन से ज्यादा समितियां ऑफिस और गोदाम से वंचित हैं।*

569 पैक्स की हुई अभी तक ऑन सिस्टम ऑडिट, रजिस्ट्रार ने दिए सर्वोच्च प्राथमिकता के निर्देश

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राज्य में प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां अर्थात पैक्स को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा हैं, अधिकतर पैक्स ई.आर.पी पोर्टल पर गो-लाइव हो चुकी हैं । इन पैक्स की ऑन सिस्टम ऑडिट एवं वार्षिक खाता बन्दी समिति के संबंधित अंकेक्षक से आवश्यक रुप से करवाने के लिए समस्त क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी एवं विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां को पूर्व में निर्देशित किया गया था । साथ ही विभाग द्वारा इस कार्य की समय-समय पर समीक्षा की जा रही हैं । सहकारिता विभाग रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने आज एक पत्र जारी कर पैक्स कंप्यूटराइजेशन में ऑन सिस्टम ऑडिट कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश प्रदान किए हैं । उन्होने समेकित पैक्स कम्प्यूटरीकरण प्रगति रिपोर्ट के आधार विशेष लेखा परीक्षक, अजमेर (4), बांरा (4), भरतपुर (7), जैसलमेर (4), जालौर, (8), झालावाड, (2), कोटा, (10), नागोर (4), सवाईमाधोपुर (5), सिरोही (10) हनुमानगढ, जयपुर, बांसवाडा, बीकानेर, श्रीगंगानगर, डुंगरपुर में प्रगति को बहुत कम एवं असंतोषजनक बताया है। साथ ही, उनके अनुसार कार्यालय विशेष लेखा परीक्षक, झुन्झनू, (80), जोधपुर (71), पाली (48), सीकर (45) में ऑडिट प्रगति संतोषजनक लेकिन अपेक्षानुरूप नहीं है। इसके अलावा सीसीबी प्रबन्ध निदेशक, अधिशाषी अधिकारी, एस.आई. टीम द्वारा पैक्स से समन्वय स्थापित कर ऑन सिस्टम ऑडिट को अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए प्रति दिवस पर्यवेक्षण व मोनेटरिंग करते हुए गो-लाईव हो चुकी पैक्स का शत-प्रतिशत ऑन सिस्टम ऑडिट आवश्यक रूप से अविलम्ब सम्पादित करवाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं ।

हर पंचायत में बनेगी ग्राम सेवा सहकारी समिति

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । जिले में हर पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन करने के लिए सहकारिता विभाग युद्ध स्तर पर तैयारियां में जुटा है। अब तक जिले में 48 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां समितियां नहीं है। इन पंचायतों में समितियां बनाने के लिए सर्वे करवाया जा रहा है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद इनके प्रस्ताव भी भिजवा दिए जाएंगे। नई समितियों के गठन के लिए राज्य सरकार ने भी बड़ी राहत दी है। अब नई ग्राम सेवा समिति के गठन के लिए 1.50 लाख रुपए हिस्सा राशि और 150 सदस्य जरूरी है। पहले हिस्सा राशि 3 लाख और सदस्यों की संख्या 300 होनी जरूरी थी। नियमों में शिथिलता के चलते हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति का गठन होने का सपना साकार हो जाएगा। हालांकि अमानत राशि पूर्व की भांति एक लाख रुपए ही जरूरी है। हर पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति बनने से किसानों को सहकारिता विभाग की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। उन्हें अपने गांव में ही खाद एवं बीज

उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साख सीमा के अनुसार अल्पकालीन फसली ऋण भी मिल जाएगा।

जानकारी के अनुसार अब तक 230 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत है। उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जालोर सुनील वीरभान ने बताया कि जिले की 48 ग्राम पंचायतों में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित हैं, जिसमें रानीवाड़ा तहसील में सर्वाधिक 13, चितलवाना एवं जसवंतपुरा में 6, जालोर, आहोर, सरनाऊ में 5 तथा भीनमाल में 3, सायला, बागोड़ा में 2 व सांचौर में 1 ग्राम पंचायत वर्तमान में ग्राम सेवा सहकारी समिति यानि पैक्स विहीन हैं।

तुरंत प्रदान की जा रही स्वीकृति

किसानों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा भी तुरंत स्वीकृति प्रदान की जा रही है। ग्राम सेवा सहकारी समितियां कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्य कर रही है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। हर पंचायत स्तर पर सहकारी समिति बनने से किसानों को गांव में ही खाद-बीज उपलब्ध हो जाएगा। उनको दूसरे गांव में जाने की समस्या से निजात मिलेगी। समिति की अन्य योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। नए सदस्यों को सहकारिता विभाग की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

सहकारिता वर्ष मनाए जाने का निर्णय

ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा रबी और खरीफ सीजन में कृषि जिंसों की खरीद भी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन के निर्देश जारी किए गए हैं जिससे जिले में सभी पंचायतों में जीएसएसएस गठन की प्रक्रिया चल रही है। सरकार द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में विशेष कार्यवाही करते हुए इन समितियों को सक्षम बनाने के लिए गोदाम स्वीकृत किए जा रहे हैं। अन्न भंडारण के लिए ये बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। अन्न भंडारण गोदाम समिति में उपलब्ध भूमि के अनुसार 500 एमटी, 250 एमटी और 100 एमटी के स्वीकृत किए जा रहे हैं। सहकार से समृद्धि के साथ-साथ वर्ष 2025 को सहकारिता वर्ष मनाए जाने का निर्णय भी सरकार ने लिया है।

ग्रामीणों को गांव में ही मिलेगी सुविधा

नई गठित होने वाली प्रत्येक समिति में 150 नए सदस्य जोड़े जाएंगे। इनको विभाग की योजनाओं का सीधा फायदा होगा। नए सदस्यों को साख सीमा के अनुसार अल्पकालीन फसली ऋण मिल सकेगा। इससे किसानों को फसल पकाने में सुविधा होगी। समय पर खाद-बीज मिलने से भी काश्तकारों को लाभ होगा। साथ ही ग्राम सेवा सहकारी समितियां ई-मित्र, जन औषधि केंद्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि का भी संचालन कर सकेंगी। इससे समिति की आय बढ़ेगी, वहीं ग्रामीणों को गांव में ही सुविधा मिलेगी।

जिले की अन्य समस्त पैक्स विहीन ग्राम पंचायतो में भी आगामी वर्ष तक ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाना है, ग्रामीणों से अपील की जाती है कि वह स्वयं भी

इस कार्य में पहल कर कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं ताकी पैक्स का यथासंभव गठन किया जा सकें ।

-सुनील वीरभान, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जालोर

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक एवं मुद्रक प्रकाश वैष्णव द्वारा वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स, वैष्णव फार्म पसावा तह. चितलवाना जिला-जालोर (राज.) 343041 से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर (जिला-जालोर) से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।